Ques – Discuss the planning problems in Tribal Regions.

Ans – जनजाति क्षेत्र का निर्धारण आसान नहीं। भारत में कोई भी परिभाषा संक्षिप्त में रखे नहीं दिया जा ~~सकता~~ सकता है। सामान्यतः जनजाति क्षेत्र के निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक विशेषताएँ होनी चाहिए –

(a) उनके निवास उस मिट्टी में अति प्राचीन काल से रहते आए हैं।
(b) वे पहाड़ियों में अलग-अलग या जंगलों में निवास करते हैं।
(c) उन्हें अपने इतिहास का बहुत धुंधला ज्ञान है। इस अर्थ में की कुछ पीढ़ी के बाद उनके इतिहास एवं धार्मिक अंधविश्वास में बहुत बदल जाते हैं।
(d) उनका आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के ज्ञान का स्तर निम्न होता है।
(e) अपने सांस्कृतिक पहलू जैसे – भाषा, विश्वास, रीति रिवाज और संस्थाओं में समाज के अन्य वर्गों से अलग रहते हैं।
(f) अतः वे किसी भी स्तर में आस-पास के क्षेत्र अनभिज्ञ रहते हैं।

उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 427 जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है। जिन्हें विशेष सुरक्षा और सुविधाएँ भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। मुख्य रूप से तीन जनजाति गोंड, भील व संथाल ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक है। उसके बाद मिनास, मुंडा और उराँव की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उसके बाद खोंड, सोण्ड, कोल आते हैं जो 5 लाख से अधिक है। वैसे ही 42 ऐसे जनजाति हैं जिनकी जनसंख्या 1 से 5 लाख है। सबसे कम आबादी जिस जनजाति की है वो ग्रेट अण्डमानिक की है जिसकी 1991 की जनगणना में सिर्फ 23 था। 1951 के जनगणना में जनजातियों की संख्या 19.17 मिलियन था जो भारत के कुल जनसंख्या का 5.29% था। 2011 की जनगणना में इनकी संख्या ~~~~ 104.2 मिलियन थी जो कुल आबादी का 8.6% था।

इन जनजातियों की आर्थिक स्थिति को विद्रोहन अर्थतंत्र एवं आदिम अर्थतंत्र कहा जा सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर यह कहा जाय कि ये जनजाति आज भी सामान्य संचय या फल संचय अवस्था से गुजर रहे हैं और इनमें कुछ घुमक्कड़ और कुछ अर्द्ध घुमक्कड़ जीवन व्यतीत क।

Scanned with CamScanner

कर रहे है । फिर भी जनजाति और सामान्य जनता के पारस्परिक मिलन और भारत सरकार के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं से उनके सुधार के प्रयास से कुछ महत्वपूर्ण जनजाति के लोग औद्योगिक श्रमिक बन सके है ।

इस प्रकार भारत में इस जनजातियों के आर्थिक विकास के कितनी अवस्थाएँ देखी जा सकती है और - अण्डमानिक जो अंडमान - निकोबार में रहते है । आज भी अन्न संग्रह अवस्था में जी रहे है । के सी सबसे अलग-थलग जनजाति Jarawa, Sentinelese इस क्षेत्र में मिलते है । ये आज भी उसी अवस्था में जी रहे है जैसा कि 1000 वर्ष पहले जी रहे थे विकसित सभ्यता का इनपर कोई प्रभाव नहीं है । अधिकांश जनजाति जो जंगलो में रहते है वे न तो अकेले रहते है और न तो स्वतंत्र रहते है इनमें बिरहोर, मलर व Kharia जनजाति है जो बिहार और उड़ीसा में रहते है । वे जंगलों से विभिन्न प्रकार के कंद, मूल, फल, मधु इकट्ठा कर लाते है । ये विभिन्न जंगली लताओं से रस्सी बनाते है और इन्हे बदलकर अन्न लेते है ।

काफी वृहद संख्या में आज के जनजाति कृषि अवस्था मे पदार्पण कर गए । जबकि कुछ पुरानी अवस्था में है । जैसे- निकोबार के Shopman| शिकार करना, जंगली सुअर को पकड़ना और खाना इनका पेशा है । ये सुअरों की मदद से छोटे-छोटे खेत जोतते है और तम्बाकू जैसा पौधा उगाते है । टोडा जनजाति भी कुछ सब्जी और अन्न की खेती शुरु कर दिए है । भारत के वृहद जनजाति अब कृषि करने लगे है क्योंकि स्थाई निवास करने वाले जनजाति इसे सबसे आसान समझते है । जैसे- गोंड जो मध्य प्रदेश के मण्डला और बस्तर में मिलते है । कुछ महाराष्ट्र, A.P., उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैलकर कृषि के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते है । ये झूम कृषि और स्थायी कृषि दोनों कर लेते है उसी तरह भील जनजाति खासकर उच्च भूमि क्षेत्र के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र में खेती करने लगे है । संथाल जिनका केन्द्रीकरण झारखंड और बिहार के संथाल परगना, भागलपुर, हजारीबाग, सिंहभूम जिलों में फैला है । दूसरी जनजाति उरॉव रांची, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में फैले है । इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाले जनजाति Nager, खासी, जयंतिया, मेघालय के निर्वाहन कृषि करते है । इस प्रकार अधिकांश

Scanned with CamScanner

जनजातियों का मुख्य आर्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण हाथ है।

भारत के जनजातीय क्षेत्रों में मुख्यतः तीन तरह के कृषि व्यवस्था अपनाई जाती है —

① झूम कृषि (पहाड़ी इलाके के तथा जंगली क्षेत्रों में)
② स्थायी कृषि (समतल क्षेत्रों में)
③ बागानी कृषि (जैसे - नारियल, चाय, अन्नानास आदि)

झूम कृषि 2.6 मिलियन जनजाति करते हैं जो लगभग 3500 वर्ग मील में फैले हुए हैं इसमें जंगलों को काट कर जलाया जाता है खेती की जाती है उर्वरता घटने पर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसमें कोई कृषि तकनीकि का प्रयोग नहीं होता। इसमें लाभ की प्रवृत्ति न होकर जीवन के साधन उपजाए जाते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि जो जनजाति स्थाई है स्थायी कृषि करते हैं वे एक ग्रामीण व्यवस्था में जीते हैं। उनका अपना आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक इकाई होता है। जैसे - संथाल में उनकी आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था 7 ऑफिसर द्वारा होती है।

① मांझी प्रमुख
② परनायक उपप्रमुख
③ नायक ग्रामीण तंत्र
④ कुदम नायक उपसंत
⑤ जोग मांझी जो सामूहिक भोज और जवानों के चरित्र को देखता है
⑥ जोग परनायक जो उपप्रमुख का सहायक होता है।
⑦ गोदत जो संदेशवाहक होता है।

पंचवर्षीय योजना में जनजाति विकास —

जनजाति की मुख्य समस्या इनकी गरीबी है जीवन स्तर निम्न होता है। भूख, कुपोषण, अशिक्षा के शिकार होते हैं। इन्हें ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनजाति विकास की कई विकास योजनाएं कृषि, सिंचाई, सहकारिता, स्वास्थ्य, आवास में बनाए। सबके लिए अलग-अलग कमिटियाँ बनाई गई जो इनके विभिन्न समस्याओं प्रखंड स्तर से लेकर केन्द्रीय स्तर तक योजनाएं बनाता है व क्रियान्वयन करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 40

पायलट प्रोजेक्ट बनाए गए। जिसमें इन जनजातियों के जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान को ध्यान में रखा गया। सभी प्रखंड को 27 लाख रुपये इनके विकास के लिए दिया गया। राज्य सरकार द्वारा भी इन्हें काफी सहायता अनुपूरक ग्रांट के रूप में दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 80.73 करोड़ रुपये रखा गया जिसमें 36.54 करोड़ शिक्षा पर, 28.95 करोड़ आर्थिक उत्थान के लिए 15.11 करोड़ स्वास्थ्य एवं आवास के लिए रखा गया।

राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा इन जनजातियों के विकास के लिए कई योजनाएँ बनाई गई जो निम्नलिखित है—

(1) केन्द्रीय पोषित योजनाएँ—
   (a) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना
   (b) लड़कियों के छात्रावास
   (c) परीक्षा के पहले प्रशिक्षण
   (d) जनजाति विकास प्रखंड
   (e) सहकारिता
   (f) शोध प्रशिक्षण और विशेष योजना
   (g) गंदे वातावरण में काम करने वाले लोगों का विकास
   (h) गैर सरकारी संस्थाओं को जो अनुसूचित जनजाति के भारतीय स्तर पर उन्हें अनुदान देगा।

(2) राज्य स्तर पर भी लगभग इसी तरह की सुविधाएँ दी गई उसके अलावा कुछ निम्न है—
   (a) स्कूल व कॉलेज फीस की माफी
   (b) शैक्षणिक उपकरण उपलब्ध कराना
   (c) मध्य दिवसीय भोजन
   (d) आश्रम स्कूल की स्थापना
   (e) होस्टल और स्कूल के बनाने के अनुदान
   (f) भूमि व सिंचाई की व्यवस्था
   (g) कुटीर उद्योग का विकास
   (h) मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन को प्रोत्साहन
   (i) स्वास्थ्य सुविधा
   (j) पेय जल की सुविधा
   (k) घर बनाने को भूमि व अनुदान और कानूनी सलाह।

Tribal development Agency Project —

Tribal development Agency Project 33

जगहों पर स्थापित किए गये। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, झारखंड के सिंहभूम, मध्य प्रदेश के डांटेवाला और केन्टा तहसील में और उड़ीसा के गनजाम और कोरापुर जिले में शुरु किया गया। इस योजना की मुख्य विशेषता यह थी—

(a) हर प्रोजेक्ट जनजाति विकास के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया जिसके सभी प्रकार के सुविधाओं के विकास की योजना बनी। इसने 2 करोड़ की राशि का बजट बनाया गया। इससे 10 हजार जनजाति परिवार को लाभांवित किया गया।

इसके अलावा कई अन्य योजनाओं को इन जनजातियों के विकास के लिए राज्य व केन्द्र सरकार के द्वारा किया गया। इसमें कोई शक नहीं इन जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार भरपूर जोर देती रही। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ऋण में ब्याज की दर में कमी, इंदिरा आवास योजना भी बनाए गए जो इन जनजातियों को प्रदान किया गया।

Scanned with CamScanner